पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सृष्टि कुमारी

बनाम

संदीप कुमार लोहानी

2016 का विविध अपील संख्या 1116

11 जुलाई 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पी. सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या परिवार न्यायालय द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर दी गई तलाक की डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

हेडनोट्स

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955- धारा 13(1)(i-ए)(i-बी)- तलाक- क्रूरता और परित्याग- विवाह विच्छेद- अपीलकर्ता का विवाह प्रतिवादी के साथ 09.06.2009 को हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार संपन्न हुआ- विवाह विधिवत संपन्न हुआ और विवाह से एक लड़की पैदा हुई- जब प्रतिवादी को दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया गया, तो वहां भी अपीलकर्ताओं ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और आईपीसी की धारा 498ए के तहत झूठा मामला दर्ज किया- विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिवादी को बरी कर दिया गया- अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच वैवाहिक संबंध पहले ही पूरी तरह से टूट चुका है और उनके वैवाहिक जीवन की बहाली की कोई उम्मीद नहीं है।

निर्णय: अपीलकर्ता-पत्नी बिना किसी उचित बहाने के 31.03.2011 से अलग रह रही है जो क्रूरता के दायरे में आता है, और इस प्रकार, वैवाहिक बंधन वास्तव में सुधार से परे है - अपीलकर्ता-पत्नी अपने मामले को केवल अपनी बेटी के पक्ष में 10,00,000/- रुपये के स्थायी गुजारा भत्ते में वृद्धि के संबंध में सीमित रखेगी - विद्वान परिवार न्यायालय ने पक्षकारों के बीच विवाह विच्छेद का आदेश पारित करके सही किया है - पक्षकारों के बीच विवाह विच्छेद का आदेश पारित करने के संबंध में विद्वान प्रधान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और आदेश को बरकरार रखा गया -

भरण-पोषण की मात्रा प्रत्येक मामले के लिए व्यक्तिपरक है और विभिन्न परिस्थितियों और कारकों पर निर्भर करती है - न्यायालयों को दोनों पक्षों की आय के कारकों पर गौर करना चाहिए; विवाह के अस्तित्व के दौरान आचरण; उनकी व्यक्तिगत सामाजिक और वित्तीय स्थिति; प्रत्येक पक्ष के व्यक्तिगत खर्च; अपने आश्रितों को बनाए रखने के लिए उनकी व्यक्तिगत क्षमता और कर्तव्य; विवाह के अस्तित्व के दौरान पत्नी द्वारा प्राप्त जीवन की गुणवत्ता; विवाह की अवधि और ऐसे अन्य समान कारक- न तो अपीलकर्ता-पति और न ही प्रतिवादी-पत्नी ने प्रधान न्यायाधीश के समक्ष अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण दाखिल किया है और पहलुओं का आकलन किए बिना और पक्षों को ठीक से सुने बिना, एक कमजोर तरीके से, नाबालिग बेटी के पक्ष में सावधि जमा के रूप में 10,00,000/- (दस लाख) रुपये जमा करने का आदेश पारित किया गया था। - नाबालिग बेटी के पक्ष में जमा/भरण-पोषण की राशि तय करने के संबंध में मामला केवल विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गया को वापस भेज दिया गया था। - निर्देश के साथ अपील का निपटारा किया गया।

(पैराग्राफ 17, 20, 23, 25)

न्याय दृष्टान्त

जगदीश सिंह बनाम माधुरी देवी, **(2008) 10 एससीसी 497**; जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जयसवाल मजूमदार, **(2021) 2 आरसीआर (सिविल)** 289; समर घोष बनाम जया घोष, **(2007) 4 एससीसी 511**; रजनीश बनाम नेहा, **(2021) 2 एससीसी 324**; अदिति उर्फ मीठी बनाम जितेश शर्मा, **(2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1451;** प्रवीण कुमार जैन बनाम अंजू जैन, **2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3678–संदर्भित किया गया।**

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

मुख्य शब्दों की सूची

तलाक, भरण-पोषण, विवाह विच्छेद, क्रूरता और परित्याग, भरण-पोषण की मात्रा

प्रकरण से उत्पन्न

वैवाहिक स्वामित्व वाद संख्या 92/2016 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गया द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2016 से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री रमा कांत सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादियों की ओर से: श्री शशिकांत अमर, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 की विविध अपील संख्या 1116

==========

सृष्टि कुमारी पति संदीप कुमार लोहानी, निवासी- गाँव-पीतेश्वर, थाना -सिविल लाइन गया, बिहार, वर्तमान में निवासी- के. पी. लेन, मदरसा के पास, थाना -कोतवाली, जिला- गया ।

... ...अपीलकर्ता/ओं

बनाम

संदीप कुमार लोहानी पिता- स्वर्गीय श्री गोपाल नंदन प्रसाद, निवासी- साटिन क्रेडिट केयर लिमिटेड, 9वीं मंजिल, कंचनजंगा बिल्डिंग, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 ।

... ...प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री रमाकांत सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री शशीकांत अमर, अधिवक्ता

==========

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पीडी. सिंह

सीएवी निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पीडी. सिंह)

तारीखः 11-07-2025

पार्टियों को सुना।

2. अपीलार्थी ने इस अपील में 2016 के वैवाहिक शीर्षक वाद संख्या 92 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , गया द्वारा दिनांक 30.06.2016 को

पारित आदेश और डिक्री के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में '1955 अधिनियम') की धारा 13 (1)(i-a)(i-b) के तहत प्रतिवादी-पति द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी गई है, जिसमें तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग करने की मांग की गई है और प्रतिवादी-पति को अपने नाबालिग बेटी अनन्या के पक्ष में उसकी शादी और अन्य उद्देश्यों के लिए सावधि जमा के रूप में 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया जिसे अदालत की अनुमति से किसी भी आवश्यकता के समय उसके द्वारा निकल लिया जाना था।

3. स्पष्ट रूप से, अपीलार्थी का विवाह हिंदू संस्कारों और समारोहों के अनुसार 09.06.2009 पर प्रत्यर्थी के साथ संपन्न किया गया था। विवाह विधिवत संपन्न हुआ और विवाह से एक कन्या-बच्चे का जन्म हुआ।

4. 1955 के अधिनियम की धारा 13 (1) (i-ए)(i-बी) के तहत दायर अपनी याचिका में प्रत्यर्थी-पति का अनुरोधित मामला यह था कि उसकी शादी अपीलार्थी-पत्नी के साथ दिनांक 09.06.2009 को समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार बिना किसी दहेज के उनके बड़ों और शुभचिंतकों की उपस्थिति में की गई थी। विवाह के समय, प्रतिवादी-पति गुड़गांव में कार्यरत थे, जबकि अपीलकर्ता-पत्नी बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत थीं। अपीलकर्ता-पत्नी ने अपना स्थानांतरण अपने बैंक की गुड़गांव शाखा में करवा लिया और मार्च, 2010 तक वहीं कार्यरत रहीं। उन्होंने गुड़गांव में अपने वैवाहिक जीवन का आनंद तब तक उठाया जब तक कि प्रतिवादी-पति के सास-ससुर ने उनके साथ स्थायी रूप से रहने के इरादे से उनके वैवाहिक जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करना शुरू नहीं कर दिया। हालाँकि, प्रतिवादी-पति ने उन्हें सभी घरेलू सुख-सुविधाएं प्रदान करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों पक्षों के वैवाहिक जीवन में उनके हस्तक्षेप ने उनके बीच और अधिक गलतफहमी पैदा कर दी। यह भी दलील दी गई है कि

अपीलार्थी-पत्नी ने अपनी 7वें महीने की गर्भावस्था में 08.03.2010 - से 31.03.2011 तक मातृत्व अवकाश लिया और प्रत्यर्थी-पति ने उसकी गर्भावस्था के दौरान उसे सभी आवश्यक सुख-सुविधाएं प्रदान कीं और 15 मई, 2010 को उसने गुड़गांव के अपोलो क्रैडल अस्पताल में अनन्या नाम की एक बच्ची को जन्म दिया, जहां सभी खर्चों की कीमत रु 1 लाख स्वयं प्रतिवादी-पति द्वारा खर्च किए गए थे। अपीलकर्ता-पत्नी ने हमेशा अपने माता-पिता की इच्छा के अनुसार उन्हें अपने वैवाहिक घर में रखने की कोशिश की और बच्ची के जन्म के बाद उनका हस्तक्षेप बढ़ गया। कई मौकों पर, अपीलार्थी-पत्नी ने उसे धमकी दी कि अगर वह उसके माता-पिता को अपने घर पर रखने के लिए सहमत नहीं हुआ तो वह अपने कार्यस्थल के पास एक अलग घर ले लेगी और अपने माता-पिता के साथ अलग रहेगी। अपीलार्थी-पत्नी हमेशा अपनी माँ की सलाह का आंख मूंदकर पालन करती थी जो उसकी इच्छाओं के खिलाफ थी। सितंबर, 2010 में, प्रतिवादी-पति को हैदराबाद में स्थानांतरित होना पड़ा, मेसर्स स्पंदना स्पूर्ति में संचालन प्रमुख के रूप में शामिल होने के लिए और वह वहाँ शामिल हो गए और उनके अनुरोध पर अपीलार्थी-पत्नी भी अपनी छुट्टी के दौरान अक्टूबर, 2010 के महीने में हैदराबाद में उनके साथ शामिल हो गईं। यह भी दलील दी गई है कि हैदराबाद में उनकी नई नौकरी में, उनके काम करने का समय और काम पर प्रतिबद्धताएं बढ़ गई थीं और अपीलकर्ता-पत्नी ने बदली हुई स्थिति को समझने के बजाय, उनके चरित्र पर संदेह करना और निराधार आरोप लगाना शुरू कर दिया था। 04-02-2011 की रात को, अपीलार्थी-पत्नी ने अपनी माँ के साथ प्रतिवादी के साथ अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हुए बहस की और उसके चरित्र पर आधारहीन गंभीर सवाल उठाए। अपीलार्थी-पत्नी बेटी अनन्या के साथ अपने सभी सामान के साथ 31-03-2011 को प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति मे अपना वैवाहिक घर छोड़ गई और अपने व्यक्तिगत सामान के साथ साथ उसने 15 लाख रुपये के उसकी माँ के सोने के गहने भी ले लिए हैंः

5. प्रतिवादी पति का आगे तर्क यह है कि 31.03.2011 को ससुराल छोड़ने के बाद, अपीलकर्ता-पत्नी ने उसी दिन यानी 31.03.2011 को अपने पति (प्रतिवादी) के खिलाफ आईपीसी की धारा 498(ए) के तहत माधोपुर पुलिस थाने में मुकदमा संख्या 184/2011 दर्ज कराया, जिसमें दहेज की मांग और मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करने का झूठा आरोप लगाया गया। प्रतिवादी द्वारा उसके खिलाफ झूठा और तुच्छ मामला दर्ज करने के कारण उसे मानसिक पीड़ा हुई। अंततः, प्रतिवादी-पति को 17 जून, 2024 को माधोपुर पुलिस थाने में दिए गए फैसले के तहत कुकटपल्ली, मियापुर के विद्वान नौवें महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा बरी कर दिया गया। मामला संख्या 184/2011 में इस टिप्पणी के साथ कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 498(ए) के तहत आरोपी प्रतिवादी के अपराध को साबित करने में सभी पहलुओं से विफल रहा है। प्रतिवादी पति ने भी धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका दायर की है। परिवार न्यायालय, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश के समक्ष 12-08-2011 को एफसीओपी संख्या 1068/2011 के तहत हिंदू विवाह अधिनियम और अपीलकर्ता-पत्नी के उपस्थित न होने पर, जब मामला एकतरफा सुनवाई के लिए नियत किया गया था, तब उसने मामले को गया, बिहार स्थानांतरित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष टीपी संख्या 695/2012 दायर की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानांतरण याचिका को खारिज कर दिया है और एफसीओपी संख्या 1068/2011 को वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए आदेश दिया गया है। अपीलकर्ता-पत्नी ने अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उसने प्रतिवादी-पति द्वारा अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए उठाए गए सभी सकारात्मक कदमों का विरोध करने का प्रयास किया और अपीलकर्ता-पत्नी ने प्रतिवादी-पति की प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति को गंभीर और स्थायी क्षति पहुँचाई। 31-03-2011 के बाद से, जब उसने बिना किसी उचित कारण के

प्रतिवादी-पति को छोड़ दिया, तब से दोनों पक्षों के बीच कोई सह-निवास नहीं है। अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच वैवाहिक संबंध पहले ही पूरी तरह से टूट चुके हैं और उनके वैवाहिक जीवन के बहाल होने की कोई उम्मीद नहीं है।

6. अपीलार्थी-पत्नी पेश हुईं और अपना लिखित बयान दाखिल किया। अपीलार्थी-पत्नी का संक्षिप्त निवेदन यह है कि प्रतिवादी के साथ अपीलार्थी का विवाह 9-05-2009 को महूरी मंडल गोसाईबाग, गया में हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार किया गया था। शादी के समय, वह बैंक ऑफ बड़ौदा के मुज़फ़्फ़रपुर में तैनात थी, जबकि प्रतिवादी-पति गुड़गांव में तैनात थे। माता-पिता और उन्होंने खुद गुड़गांव में उनके स्थानांतरण के लिए आवेदन किया, जहां उनके पति (प्रतिवादी) तैनात थे। अपीलार्थी ने अपोलो क्रैडल अस्पताल में 15-05-2010 को एक कन्या बच्चे को जन्म दिया और उन्होंने अनन्या के जन्म के दौरान संयुक्त रूप से खर्चों को पूरा किया। अनन्या के जन्म के दौरान अपीलार्थी-पत्नी के माता-पिता ने भी उसकी और उसके नवजात शिशु की देखभाल की और उन्होंने कभी भी अपनी बेटी के वैवाहिक संबंधों में खलल डालने का कोई प्रयास नहीं किया। यह भी दलील दी गई है कि प्रतिवादी-पति ने सितंबर, 2010 में खुद को हैदराबाद स्थानांतरित कर लिया और वहां रहना शुरू कर दिया। प्रत्यर्थी-पति ने बिना किसी कारण के अपीलार्थी-पत्नी पर बेरहमी से हमला किया, जिसके कारण वह प्रत्यर्थी-पति के खिलाफ 2011 का माधोपुर पी. एस. मामला संख्या 184 दर्ज करने के लिए मजबूर हो गई और जब अपीलार्थी-पत्नी को अपना जीवन असुरक्षित लगा तो वह गया वापस आ गई और बैंक में काम करना शुरू कर दिया। प्रतिवादी-पति ने गलत पता देकर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मामला दर्ज किया है और उसके पक्ष में एकतरफा आदेश प्राप्त किया है। उन्होंने 2011 के माधोपुर पी. एस. मामला संख्या 184 में भी खुद को बरी करा लिया क्योंकि अपीलार्थी-पत्नी के पक्ष

में लड़ने के लिए कोई नहीं था क्योंकि अपीलार्थी-पत्नी गया से मामला लड़ने में सक्षम नहीं थी। नाबालिग बच्चा अनन्या कई बीमारियों से पीड़ित है और प्रतिवादी-पति ने कभी भी पिता के रूप में जिम्मेदारी नहीं ली और न ही हैदराबाद में अपने नाबालिग-बच्चे के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। विवाह के बाद, अपीलार्थी-पत्नी को पता चला कि प्रत्यर्थी-पति पहले श्रीमती शाली सेठ पिता नरेंद्र कुमार के साथ विवाहित था और उसने सितंबर, 2007 में उसके खिलाफ तलाक का झूठा फरमान प्राप्त किया।

7. मुकदमे के समापन के बाद, परिवार न्यायालय, गया के विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी-संदीप कुमार लोहानी तलाक की डिक्री के हकदार हैं। इसलिए, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाह को भंग कर दिया गया और प्रत्यर्थी-पति को 10,00,000-(दस लाख) रुपये अपनी नाबालिग बेटी अनन्या के पक्ष में उसकी शादी और अन्य उद्देश्यों के लिए सावधि जमा के रूप में फिक्स करने का निर्देश दिया गया। विद्वान परिवार न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित अपीलार्थी-पत्नी ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की।

8. क्रूरता और त्याग के आधार पर तलाक दिया गया है। विवादित फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि परिवार न्यायालय द्वारा क्रूरता और पलायन के निम्नलिखित कृत्यों पर विचार किया गया था, जैसा कि साबित हुआः.

क) क्रूरताः

(i) मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि इस जोड़े की शादी लगभग सात साल पहले हुई थी। शादी 09.06.2009 पर हुई और वे 31.03.2011 से अलग-अलग रह रहे हैं।

(ii) यह स्वीकृत है कि दोनों पक्ष 31.03.2011 को अलग हो गए और अपीलार्थी-पत्नी ने अपने पति (प्रतिवादी) के खिलाफ 2011 का माधोपुर पी. एस. मामला संख्या 184 दायर किया है।

(iii) उच्चतम न्यायालय ने "जगबीर सिंह बनाम निशा", (2015) 9 आर. सी. आर. (सिविल) 873, "ऋषिपाल बनाम लक्ष्मी देवी", (2009) 4 आर. सी. आर. (सिविल) 811, “धर्मपाल बनाम श्रीमती पुष्प देवी "2004 आर. सी. आर. (सिविल) 717, "मेजर आशीष पूनिया श्रीमती नीलिमा पूनिया"; "मंगयाकारसी बनाम एम. युवराज" (2020) 3 एस. सी. सी. 786, "के. श्रीनिवास राव बनाम डी. ए. दीपा" (2013) 5 एस. सी. सी. 226 और "के. श्रीनिवास बनाम के. सुनीता" (2014) 16 एस. सी. सी. 34 में माना है कि पति या पत्नी या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ निराधार आरोप लगाना और झूठी शिकायतें दर्ज करना दूसरे पति या पत्नी के प्रति क्रूरता के समान है और कहा है कि अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक मामले में प्रतिवादी-पति और उसकी मां को बरी करना वास्तव में यह दर्शाता है कि प्रतिवादी-पति ने वास्तव में अपीलार्थी-पत्नी के हाथों वैवाहिक क्रूरता का सामना किया है।

(v) परिवार न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि दंपति लगभग पाँच वर्षों से अलग रह रहे हैं और इस लंबे अलगाव ने वास्तव में उन्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि वैवाहिक बंधन टूट गया है। यह आगे देखा गया कि दंपति के एक साथ रहने की कोई संभावना नहीं है और इस तरह की शादी अब अव्यवहारिक है और यदि इसे जारी रखने की अनुमति दी जाए तो यह पार्टियों के लिए बहुत दुख का स्रोत हो सकता है।

9. तदनुसार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिवादी-पति क्रूरता का आधार साबित करने में सक्षम रहा है।

ख) परित्याग:

(i) परिवार न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी-पत्नी ने अपना वैवाहिक घर 31.03.2011 को छोड़ दिया और तब से वे अलग रह रहे हैं। अपीलार्थी-पत्नी की ओर से प्रत्यर्थी-पति के गुट में लौटने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। हालाँकि प्रतिवादी-पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका दायर की है, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल हो गए क्योंकि अपीलकर्ता-पत्नी उस मामले को लड़ने के लिए उपस्थित नहीं हुई।

(ii) यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलार्थी-पत्नी ने रिश्ते को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया था और उत्तरदाता-पति के साथ में शामिल नहीं हुई थी। उत्तरदाता-पति उन्होंने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए 1955 के अधिनियम की धारा 9 के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अलगाव का तथ्य, सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का इरादा, यह स्थापित करने के लिए जाता है कि अपीलार्थी-पत्नी ने प्रतिवादी-पति को लगातार दो साल से अधिक की अवधि के लिए छोड़ दिया है।

10. उपरोक्त परिस्थितियों में, इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की गई है।

11. अपीलार्थी-पत्नी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान परिवार न्यायालय ने प्रतिवादी-पति द्वारा दायर तलाक याचिका को अनुमति देने में कानून और तथ्यों में गलती की है। प्रतिवादी-पति स्वभाव से क्रूर है और वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता है जो उसकी उच्च महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अपीलकर्ता-पत्नी पर बेरहमी से हमला करता था,

जिसे उसके खिलाफ 2011 का माधोपुर पी. एस. मामला संख्या 184 दर्ज करने और अपनी जान बचाने के लिए मजबूर किया गया था, वह हैदराबाद से चली गई और अपने नाबालिग बच्चे अनन्या के साथ गया लौट आई। प्रत्यर्थी-पति ने इस तथ्य को भी छुपाया कि अपीलार्थी से शादी करने से पहले, उन्होंने शेली सेठ के साथ अपनी पहली शादी की थी। याचिकाकर्ता ने अपीलार्थी-पत्नी के गलत पते/विवरण का उल्लेख करते हुए हैदराबाद में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत गुप्त रूप से मामला दायर किया, जिसमें अपीलार्थी उपस्थित नहीं हो सकी और मामले की एकतरफा सुनवाई की गई और प्रतिवादी-पति के पक्ष में फैसला सुनाया गया।

12. हमने पक्षों को सुना है और पेपर-बुक के साथ-साथ विवादित फैसले का भी अध्ययन किया है।

13. इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होता हैः"क्या परिवार न्यायालय द्वारा क्रूरता और त्याग के आधार पर दिए गए तलाक के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

14. **"जगदीश सिंह बनाम माधुरी देवी", (2008) 10 एस. सी. सी. 497**, माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के दायरे पर विचार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः.

> *"24. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में शक्ति का प्रयोग कर रहा था और इसलिए यह न्यायालय के लिए न केवल कानून के प्रश्नों बल्कि तथ्य के प्रश्नों में भी प्रवेश करने के लिए खुला था। यह तय किया गया कानून है कि एक*

अपील मुकदमे की निरंतरता है। इस प्रकार अपील मुख्य मामले की पुनः सुनवाई है और अपीलीय न्यायालय सम्पूर्ण साक्ष्य का "मौखिक एवं दस्तावेजी" रूप से पुनः मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन एवं समीक्षा कर सकता है तथा अपने निष्कर्ष पर पहुंच सकता है।

25. हालाँकि, इसके साथ ही, अपीलीय न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह मौखिक साक्ष्य पर निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को ध्यान में रखे। यह नहीं भूलना चाहिए कि निचली अदालत के पास गवाहों के व्यवहार को देखने का एक लाभ और अवसर था और इसलिए, निचली अदालत के निष्कर्षों को आम तौर पर बाधित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलीय न्यायालय के पास मूल न्यायालय के समान ही शक्तियां हैं, लेकिन उनका उपयोग उचित देख रेख, सावधानी और एहतियात के साथ किया जाना चाहिए। जब निचली अदालत द्वारा तथ्य का निष्कर्ष मुख्य रूप से मौखिक साक्ष्य की सराहना पर दर्ज किया गया है, तो इसे तब तक हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि साक्ष्य के मूल्यांकन में निचली अदालत का दृष्टिकोण गलत, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत या अनुचित न हो।"

15. इसके अलावा, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(आई-ए) के अर्थ के भीतर क्रूरता की अवधारणा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समझाया गया है। **"जयदीप मजूमदार बनाम भारती जयस्वाल मजूमदार", (2021) 2 आर. सी. आर. (सिविल) 289**, निम्नानुसार अवलोकन करकेः

> *"10. मानसिक क्रूरता का आरोप लगाने वाले जीवनसाथी के कहने पर विवाह विच्छेद पर विचार करने के लिए, ऐसी मानसिक क्रूरता का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि वैवाहिक संबंध को जारी रखना संभव न हो। दूसरे शब्दों में, अन्यायपूर्ण पक्ष से इस तरह के आचरण को माफ करने और अपने जीवनसाथी के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सहिष्णुता की डिग्री एक जोड़े से दूसरे में भिन्न होगी और अदालत को पृष्ठभूमि, शिक्षा के स्तर और पक्षों की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कथित क्रूरता विवाह के विघटन को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है, अन्यायपूर्ण पक्ष के कहने पर।"*

16. "**समर घोष बनाम जया घोष", (2007) 4 एससीसी 511**, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उदाहरणात्मक मामले दिए जहां मानसिक क्रूरता का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इस बात पर जोर देते हुए कि कोई समान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक मामले का निर्णय अपने तथ्यों पर करना होगा।

"85. मार्गदर्शन के लिए कभी भी एक समान मानक निर्धारित नहीं किया जा सकता है, फिर भी हम मानव व्यवहार के कुछ उदाहरणों को गिनना उचित समझते हैं जो 'मानसिक क्रूरता' के मामलों से निपटने में प्रासंगिक हो सकते हैं। बाद के पैराग्राफ में बताए गए उदाहरण केवल उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।

(i) पक्षों के पूर्ण वैवाहिक जीवन पर विचार करने पर, तीव्र मानसिक पीड़ा, वेदना और कष्ट जो पक्षों के लिए एक-दूसरे के साथ रहना संभव नहीं बनाती है, मानसिक क्रूरता के व्यापक मानकों के भीतर आ सकती है।

(ii) पक्षों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन के व्यापक मूल्यांकन पर, यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि स्थिति ऐसी है कि पीड़ित पक्ष को इस तरह के आचरण को सहन करने और दूसरे पक्ष के साथ रहने के लिए उचित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

(iii) केवल ठंडक या स्नेह की कमी क्रूरता नहीं हो सकती, भाषा की बार-बार अशिष्टता, तरीके की लापरवाही, उदासीनता और उपेक्षा इस हद तक पहुंच सकती है कि यह दूसरे पति या पत्नी के लिए वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से असहनीय बना देता है।

(iv) मानसिक क्रूरता मन की एक अवस्था है। लंबे समय तक दूसरे के आचरण के कारण एक जीवनसाथी में गहरी पीड़ा, निराशा, हताशा की भावना मानसिक क्रूरता का कारण बन सकती है।

(v) पति या पत्नी को प्रताड़ित करने, अपमानित करने या दयनीय जीवन देने के लिए गणना किए गए

अपमानजनक और अपमानजनक व्यवहार का एक निरंतर पाठ्यक्रम।

(vi) एक पति या पत्नी का अनुचित आचरण और व्यवहार जो वास्तव में दूसरे पति या पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जिस उपचार की शिकायत की गई है और जिसके परिणामस्वरूप खतरा या आशंका बहुत गंभीर, पर्याप्त और भारी होनी चाहिए।

(vii) निरंतर निंदनीय आचरण, अध्ययन की गई उपेक्षा, उदासीनता या वैवाहिक दया के सामान्य मानक से पूर्ण विचलन, जिससे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है या पर पीड़क आनंद प्राप्त होता है, भी मानसिक क्रूरता के बराबर हो सकता है।

(viii) आचरण ईर्ष्या, स्वार्थ, स्वामित्व से बहुत अधिक होना चाहिए, जो नाखुशी और असंतोष का कारण बनता है और भावनात्मक परेशानी मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने का आधार नहीं हो सकता है।

(ix) केवल मामूली चिड़चिड़ापन, झगड़े, दैनिक जीवन में होने वाला वैवाहिक जीवन का सामान्य पतन मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

(x) वैवाहिक जीवन की समग्र रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और वर्षों की अवधि में कुछ छिटपुट मामले क्रूरता के बराबर नहीं होंगे। दुर्व्यवहार काफी लंबी अवधि के लिए निरंतर होना चाहिए, जहां संबंध इस हद तक बिगड़ गए हैं कि पति या पत्नी के कृत्यों और व्यवहार के कारण, पीड़ित पक्ष को अब दूसरे पक्ष के साथ रहना बेहद

मुश्किल लगता है, जो मानसिक क्रूरता के बराबर हो सकता है।

(xi) यदि कोई पति बिना चिकित्सा कारणों के और अपनी पत्नी की सहमति या जानकारी के बिना नसबंदी के ऑपरेशन के लिए खुद को प्रस्तुत करता है और इसी तरह यदि पत्नी चिकित्सा कारण के बिना या अपने पति की सहमति या जानकारी के बिना नसबंदी या गर्भपात कराती है, तो जीवनसाथी का ऐसा कार्य मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।

(xii) बिना किसी शारीरिक अक्षमता या वैध कारण के काफी समय तक संभोग करने से इनकार क्रूरता करने का एकतरफा निर्णय हो सकता है।

(xiii) विवाह के बाद पति या पत्नी में से किसी का भी विवाह से संतान न होने का एकतरफा निर्णय क्रूरता हो सकती है।

(xiv) जहां निरंतर अलगाव की एक लंबी अवधि रही है, यह उचित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैवाहिक बंधन सुधार से परे है। विवाह एक काल्पनिक बात बन जाती है, हालांकि एक कानूनी बंधन द्वारा समर्थित है। उस बंधन को तोड़ने से इनकार करने से, ऐसे मामलों में कानून, विवाह की पवित्रता की सेवा नहीं करता है; इसके विपरीत, यह पक्षों की भावनाओं और भावनाओं के लिए बहुत कम सम्मान दिखाता है। ऐसी स्थितियों में, यह मानसिक क्रूरता का कारण बन सकता है।"

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर जब हम पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में वर्तमान मामले की जांच करते हैं,

तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी-पत्नी किसी भी उचित बहाने के बिना 31.03.2011 से अलग रह रही है जो क्रूरता के दायरे में आता है और इस प्रकार वैवाहिक बंधन वस्तुतः सुधार से परे है। इसलिए, इस परिस्थिति में, यदि तलाक नहीं दिया जाता है, तो यह शादी की पवित्रता को पूरा नहीं करेगा।

18. इसके अलावा, इस न्यायालय ने दिनांक 24.09.2024 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को अपील में संशोधन के लिए अंतर्वर्ती आवेदन दायर करने का निर्देश दिया था क्योंकि अपीलार्थी के विद्वान वकील ने निर्देश पर प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी केवल रुपये 10,00,000 की स्थायी गुजारा भत्ता अपनी बेटी के पक्ष में बढ़ाने के संबंध में अपने मामले को प्रतिबंधित करेगा। आदेश का प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैः.

> *"4. इस स्तर पर, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने निर्देश पर प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी केवल रुपये 10,00,000 की स्थायी गुजारा भत्ता अपनी बेटी के पक्ष में बढ़ाने के संबंध में अपने मामले को प्रतिबंधित करेगा। अभिवचनों के अवलोकन में, कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि वर्तमान अपील वृद्धि के लिए है। वर्तमान अपील के लंबित रहने की अवधि को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को वर्तमान अपील के संशोधन के लिए अंतर्वर्ती आवेदन दायर करने की अनुमति है।"*

19. चल रही चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रतिवादी-पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-ए)(i-बी) के तहत उल्लिखित आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री देने के लिए एक मामला बनाया है।

20. परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हमारे सुविचारित विचार में, विद्वान परिवार न्यायालय ने पक्षों के बीच विवाह के विघटन की डिक्री को सही

ढंग से पारित किया है और हम इस बात का कोई कारण नहीं देखते हैं कि क्यों, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों को बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए। इसलिए, 2016 के वैवाहिक शीर्षक वाद संख्या 92 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गया द्वारा पारित दिनांक 30.06.2016 के विवादित निर्णय और डिक्री को पक्षकारों के बीच विवाह के विघटन के लिए एक डिक्री पारित करने के संबंध में बरकरार रखा जाता है।

21. इस आदेश के साथ भाग लेने से पहले, यहां यह ध्यान रखना उचित है कि तलाक की डिक्री देते समय, पक्षों की संपत्ति और देनदारियों का आकलन किए बिना, विद्वान परिवार अदालत ने प्रतिवादी-पति को रुपये 10,00,000-(दस लाख) उसकी नाबालिग बेटी-अन्न्या के पक्ष में सावधि जमा के रूप में जमा करने का निर्देश दिया है। न तो अपीलार्थी और न ही प्रतिवादी ने अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण दायर किया है और न ही यह विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा उसकी नाबालिग बेटी अनन्या के पक्ष में 10 लाख रुपये जमा करने का आदेश देते समय आवश्यक समझा गया था।

22. यहाँ 1955 के अधिनियम की धारा 26 का उल्लेख करना उचित है, जो इस प्रकार हैः

> ***"26. बच्चों की अभिरक्षा*** *किसी भी मामले में इस अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए, अदालत समय-समय पर ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकती है और डिक्री में ऐसे प्रावधान कर सकती है जो वह नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा, रखरखाव और शिक्षा के संबंध में न्यायसंगत और उचित समझे, जहां भी संभव हो, उनकी इच्छाओं के अनुरूप, और डिक्री के बाद, इस उद्देश्य के लिए याचिका द्वारा आवेदन करने पर, समय-समय पर ऐसे बच्चों की अभिरक्षा, रखरखाव और शिक्षा के संबंध में ऐसे सभी आदेश*

और प्रावधान कर सकती है जो ऐसे डिक्री या अंतरिम आदेशों द्वारा किए गए हो सकते हैं, यदि ऐसी डिक्री प्राप्त करने की कार्यवाही अभी भी लंबित थी, और अदालत समय-समय पर पहले किए गए ऐसे किसी भी आदेश और प्रावधानों में बदलाव या रद्द भी कर सकती है, या निलंबित भी कर सकती है।

23. भरण-पोषण की राशि प्रत्येक मामले के लिए व्यक्तिपरक होती है और विभिन्न परिस्थितियों और कारकों पर निर्भर करती है। न्यायालय को दोनों पक्षों की आय; विवाह के दौरान आचरण; उनकी व्यक्तिगत सामाजिक और वित्तीय स्थिति; प्रत्येक पक्ष के व्यक्तिगत खर्च; अपने आश्रितों का भरण-पोषण करने की उनकी व्यक्तिगत क्षमता और कर्तव्य; विवाह के दौरान पत्नी द्वारा भोगी गई जीवन की गुणवत्ता; विवाह की अवधि और ऐसे ही अन्य कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। न तो अपीलकर्ता-पति और न ही प्रतिवादी-पत्नी ने अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, गया के समक्ष प्रस्तुत किया है और उपरोक्त पहलुओं का आकलन किए बिना और पक्षों को ठीक से सुने बिना, एक कमजोर तरीके से, 30.06.2016 के आदेश द्वारा प्रतिवादी-पति की नाबालिग बेटी के पक्ष में सावधि जमा के रूप में 10,00,000/- (दस लाख) रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था। इस निष्कर्ष पर पहुँचने का आधार क्या है, यह आक्षेपित निर्णय से स्पष्ट नहीं है। पत्नी/आश्रितों को स्थायी गुजारा भत्ता देने का निर्देश दोनों पक्षों की सामाजिक, वित्तीय स्थिति का आकलन करने के बाद और साथ ही पति या पत्नी पर पड़ने वाले दायित्वों के भार को समझने के बाद दिया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रजनीश बनाम नेहा मामले (2021) 2 एससीसी 324** में दर्ज, **अदिति @ मिठी बनाम जितेश शर्मा (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1451** में दर्ज, **प्रवीण कुमार**

जैन बनाम अंजू जैन (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3678 में दर्ज) के साथ पढ़े गए मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में। **रजनीश बनाम नेहा (सुप्रा)** मामले में पारित निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:-

> *"**27**. एच. ए. एम. ए. की धारा 20 बच्चों और वृद्ध माता-पिता के रखरखाव का प्रावधान करती है। धारा 20 एक हिंदू पुरुष पर एक अविवाहित बेटी को बनाए रखने का वैधानिक दायित्व डालती है, जो अपनी कमाई या अन्य संपत्ति से खुद को बनाए रखने में असमर्थ है। अभिलाषा बनाम प्रकाश और अन्य मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि धारा 20 (3) हिंदू कानून के सिद्धांतों की मान्यता है, विशेष रूप से एक अविवाहित बेटी को बनाए रखने के लिए पिता का दायित्व। यह अधिकार व्यक्तिगत कानून के तहत निरपेक्ष है, जिसे इस अधिनियम द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई है। अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत बच्चों को भरण-पोषण के पंचाट के बीच के अंतर को नोट किया, जो एक बच्चे के भरण-पोषण के दावे को तब तक सीमित करता है, जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाता। हालाँकि, यदि कोई अविवाहित बेटी किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण खुद को बनाए रखने में असमर्थ है, तो धारा 125(1)(ग), के तहत (1)(पिता उसके वयस्कता प्राप्त करने के बाद भी उसका पालन-पोषण करने के लिए बाध्य*

होगा। एच. ए. एम. ए. के तहत विचारित रखरखाव एक व्यापक अवधारणा है। धारा 3 (बी) में विवाह के खर्च सहित भरण-पोषण की एक समावेशी परिभाषा शामिल है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का उद्देश्य और उद्देश्य संक्षिप्त कार्यवाही में पत्नी और बच्चों को तत्काल राहत प्रदान करना है, जबकि एच. ए. एम. ए. की धारा 3 (बी) के साथ पठित धारा 20 के तहत, एक बहुत बड़े अधिकार पर विचार किया गया है, जिसके लिए एक दीवानी अदालत द्वारा निर्धारण की आवश्यकता है।

***28**. धारा 22 आश्रितों के रखरखाव का प्रावधान करती है। धारा 23 में प्रावधान है कि रखरखाव प्रदान करते समय, न्यायालय को उसमें उल्लिखित मानदंडों का उचित ध्यान रखना होगाः*

23. भरण पोषण की राशि-

(1) यह निर्धारित करना न्यायालय के विवेकाधिकार में होगा कि क्या इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई और यदि ऐसा है तो क्या भरण-पोषण दिया जाएगा, और ऐसा करने में, न्यायालय को, जहां तक वे लागू हों, उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में निर्धारित विचार पर उचित ध्यान देना होगा।

(2) इस अधिनियम के तहत किसी पत्नी, बच्चों या वृद्ध या अशक्त माता-पिता को दिए जाने वाले भरण-पोषण, की राशि

निर्धारित करने में यदि कोई हो, तो निम्न को ध्यान में रखना होगा -

(क) पक्षों की पद और स्थिति को;

(ख) दावेदार की उचित इच्छाएँ;

(ग) यदि दावेदार अलग रह रहा है, तो क्या दावेदार ऐसा करने में उचित है;

(घ) दावेदार की संपत्ति का मूल्य और ऐसी संपत्ति, या दावेदार की अपनी कमाई या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई आय;

(ङ) इस अधिनियम के तहत भरण-पोषण के हकदार व्यक्तियों की संख्या।

(3) इस अधिनियम के तहत किसी आश्रित को दिए जाने वाले रखरखाव की राशि, यदि कोई हो, का निर्धारण करते समय, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा -

(क) मृतक के ऋणों के भुगतान का प्रावधान करने के बाद उसकी संपत्ति का शुद्ध मूल्य;

(ख) आश्रित के संबंध में मृतक की वसीयत के तहत किया गया प्रावधान, यदि कोई हो;

(ग) दोनों के बीच संबंधों की डिग्री;

(घ) आश्रित की उचित इच्छाएँ;

(ई) आश्रित और मृतक के बीच पिछले संबंध;

(च) आश्रित की संपत्ति का मूल्य और ऐसी संपत्ति से, या उसकी कमाई से या किसी अन्य मार्ग से प्राप्त कोई आय;

(छ) इस अधिनियम के तहत भरण-पोषण के हकदार आश्रितों की संख्या।

***35.** संशोधित धारा 125 इस प्रकार है:*

125. पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण पोषण के लिए आदेश।

(1) यदि कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, उपेक्षा करता है या रखने से इनकार करता है -

(क) उसकी पत्नी, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

(ख) उसका वैध या अवैध नाबालिग बच्चा, चाहे वह विवाहित हो या नहीं, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, या

(ग) उसका वैध या अवैध बच्चा (जो विवाहित बेटी नहीं है) जो वयस्क हो गया है, जहां ऐसा बच्चा किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण खुद को बनाए रखने में असमर्थ है, या

(घ) उसके पिता या माता, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं,

तो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या अस्वीकृति के प्रमाण पर, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या माता के भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है, ऐसी मासिक दर पर जो ऐसा मजिस्ट्रेट उचित समझे, और उसी का भुगतान ऐसे व्यक्ति को करने का आदेश दे सकता है जिसे मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देश दे:

बशर्ते कि मजिस्ट्रेट खंड (ख) में निर्दिष्ट नाबालिग लड़की के पिता को ऐसा भत्ता देने का आदेश दे सकता है, जब तक कि वह अपनी वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेती है, यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी नाबालिग लड़की के पति, यदि विवाहित है, के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं:

बशर्ते कि मजिस्ट्रेट, इस उप-धारा के तहत भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या मां के अंतरिम भरण-पोषण और ऐसी कार्यवाही के खर्चों के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझता है, और उसी का भुगतान ऐसे व्यक्ति को करने का आदेश दे सकता है जिसे मजिस्ट्रेट समय-समय पर निर्देश दे:

बशर्ते कि अंतरिम मासिक भत्ते और कार्यवाही के लिए भरण पोषण और खर्च का आवेदन का निपटान, दूसरे परंतुक के तहत जहां तक संभव हो, ऐसे व्यक्ति को आवेदन की सूचना की सेवा की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए -

(क) "नाबालिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के प्रावधानों के तहत ऐसा माना जाता है कि उसने अपना बहुमत प्राप्त नहीं किया है;

(ख) "पत्नी" में एक ऐसी महिला शामिल है जिसका अपने पति से तलाक हो गया है या जिसने तलाक ले लिया है और उसने फिर से शादी नहीं की है।

(2) रखरखाव या अंतरिम रखरखाव और कार्यवाही के खर्चों के लिए ऐसा कोई भी भत्ता आदेश की तारीख से, या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है, तो रखरखाव या अंतरिम रखरखाव और कार्यवाही के खर्चों के लिए आवेदन की तारीख से देय होगा।

(3) यदि ऐसा आदेश दिया गया कोई व्यक्ति, आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है, तो ऐसा कोई मजिस्ट्रेट, आदेश के प्रत्येक भंग के लिए, जुर्माना लगाने के लिए उपबंधित रीति से देय

रकम वसूलने के लिए वारंट जारी कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को, वारंट के निष्पादन के पश्चात्, यथास्थिति, भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण तथा कार्यवाही के व्यय के लिए प्रत्येक माह के भत्ते के संपूर्ण या उसके किसी भाग के लिए, जो भुगतान नहीं किया गया है, कारावास की सजा दे सकता है, जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकेगी या जब तक भुगतान पहले नहीं कर दिया जाता है:

बशर्ते कि इस धारा के तहत देय किसी भी राशि की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि अदालत को उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी राशि वसूल करने के लिए आवेदन नहीं किया जाता है जिस दिन वह देय हुई थीः बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को उसके साथ रहने की शर्त पर रखने की पेशकश करता है, और वह उसके साथ रहने से इनकार करती है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा बताए गए इनकार के किसी भी आधार पर विचार कर सकता है, और इस तरह के प्रस्ताव के बावजूद इस धारा के तहत आदेश दे सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए उचित आधार है।

स्पष्टीकरण-यदि किसी पति ने किसी अन्य महिला के साथ विवाह किया है या किसी रखैल को रखा है, तो यह उसकी पत्नी द्वारा

उसके साथ रहने से इनकार करने के लिए एक उचित आधार माना जाएगा।

(4) कोई भी पत्नी अपने पति से रखरखाव या अंतरिम रखरखाव और कार्यवाही के खर्चों के लिए भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी, इस धारा के तहत यदि वह व्यभिचार में रह रही है, या यदि, बिना किसी पर्याप्त कारण के, वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं।

(5) इस बात के प्रमाण पर कि कोई भी पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के तहत आदेश दिया गया है, व्यभिचार में रह रही है, या कि पर्याप्त कारण के बिना वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या कि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, मजिस्ट्रेट आदेश को रद्द कर देगा।

(जोर दिया गया) "

24. तदनुसार, हम नाबालिग बेटी अनन्या के पक्ष में जमा/भरण-पोषण की राशि तय करने के संबंध में मामले को विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवार न्यायालय, गया के पास वापस भेजना उचित समझते हैं। निचली अदालत प्रतिवादी पति और अपीलकर्ता-पत्नी को निर्देश देगी कि वे **रजनीश बनाम नेहा (2021) 2 एससीसी 324** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में अपनी संपत्ति और देनदारियों के बारे में विवरण दाखिल करें, जिसे **अदिति @ मिठी बनाम जितेश शर्मा (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1451** के साथ पढ़ा जाए, जिसे **प्रवीण कुमार जैन**

बनाम अंजू जैन (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3678 के साथ पढ़ा जाए) के मामले में सुनाया गया है और उनकी संपत्ति और देनदारियों का विश्लेषण करने के बाद, निर्णय पारित होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करें। दोनों पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटान में सहयोग करें। किसी भी पक्ष के उपस्थित न होने की स्थिति में, विधि के अनुसार उचित आदेश पारित किया जाएगा।

25. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, एम.ए. संख्या 1116/2016 का निपटारा किया जाता है।

26. लंबित अंतरवर्ती आवेदन (आई.ए.), यदि कोई हो का निपटारा किया जाता है।

(एस. बी. पीडी सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।